शुगर मिलों को फाइनेंशियल पैकेज देने का इशारा

इंडस्ट्री को आर्थिक दिक्कतों से उबारने के लिए केंद्र सरकार कर रही विचार

[पीटीआई *नई दिल्ली*]

उत्तर प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री में चल रहे संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि वह आर्थिक दिक्कत से जूझ रही चीनी मिलों के लिए फाइनेंशियल पैकेज पर काम कर रही है। साथ ही, केंद्र सरकार ने राज्यों को रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को भी लागू करने को कहा है, जिसके तहत गन्ने की कीमत को शुगर प्राइस से लिंक करने की बात प्रमुखता से कही गई है।

केंद्र सरकार ने मई में 80,000 करोड़ रुपये के शुगर सेक्टर को आंशिक तौर पर डी-कंट्रोल करने का फैसला किया था। इसके तहत शुगर मिलों को चीनी बेचने की आजादी दी गई थी और इनके लिए देशभर के राशन दुकानों को सब्सिडाइज्ड शुगर सप्लाई करने की अनिवार्यता खत्म करने का निर्देश दिया गया था।

फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने बताया, 'हमने अपना काम कर दिया है। कोई लेवी नहीं है। कोई रिलीज सिस्टम नहीं है। रंगराजन कमेटी की तरफ से की गई 8 सिफारिशों में से बाकी राज्यों के अधिकार के हैं। मसलन प्रॉफिट का बंटवारा और अन्य चीजें।' रंगराजन कमेटी ने गन्ने के रेट को शुगर की कीमत से लिंक करने की सिफारिश की थी, जिसे राज्य सरकारों ने अब तक लागू नहीं किया गया है। के

राज्यों को निर्देश

- केंद्र सरकार ने राज्यों को रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को भी लागू करने को कहा है, जिसके तहत गन्ने की कीमत को शुगर प्राइस से लिंक करने पर जोर दिया गया है
- केंद्र सरकार ने मई में 80,000 करोड़ रुपये के शुगर सेक्टर को आंशिक तौर पर डी-कंट्रोल करने का फैसला किया था। इसके तहत शुगर मिलों को चीनी बेचने की आजादी दी गई थी
- देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने ऑपरेशन नहीं शुरू करने का फैसला किया है

वी थॉमस ने कहा, 'रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए हमने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है। प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए।' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस मामले में और ज्यादा अधिकार नहीं हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने ऑपरेशन नहीं शुरू करने का फैसला किया है। मिलों का कहना है कि सरकार की तरफ से गन्ने की तय राशि व्यावहारिक नहीं है।

राज्य की चीनी मिलों ने बताया कि वे गन्ना किसानों को 225 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते, जबकि राज्य सरकार ने बुधवार को गन्ने के लिए 280 रुपये प्रति क्विंटल के स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (एसएपी) का ऐलान किया था। मिलों को मुश्किल से उबारने की इंडस्ट्री की डिमांड के बारे में पूछे जाने पर थॉमस ने कहा, 'चीनी मिलों के लिए फाइनेंशियल पैकेज जैसा कुछ होना चाहिए, जिस पर हम काम कर रहे हैं।'

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार शुगर मिलों की समस्याओं से वाकिफ है। उन्होंने कहा, 'हमने इस संबंध में एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठक की है और उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी है।' शुगर इंडस्ट्री को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने फ्री लोन समेत तमाम उपायों पर चर्चा की थी। इस बारे में मंत्रियों के ग्रुप की अनौपचारिक बैठक के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पावर ने कहा था, 'चीनी की कीमत गिर गई है और इस वजह से शुगर इंडस्ट्री को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें 3-4 वैकल्पिक उपायों पर चर्चा की गई।'

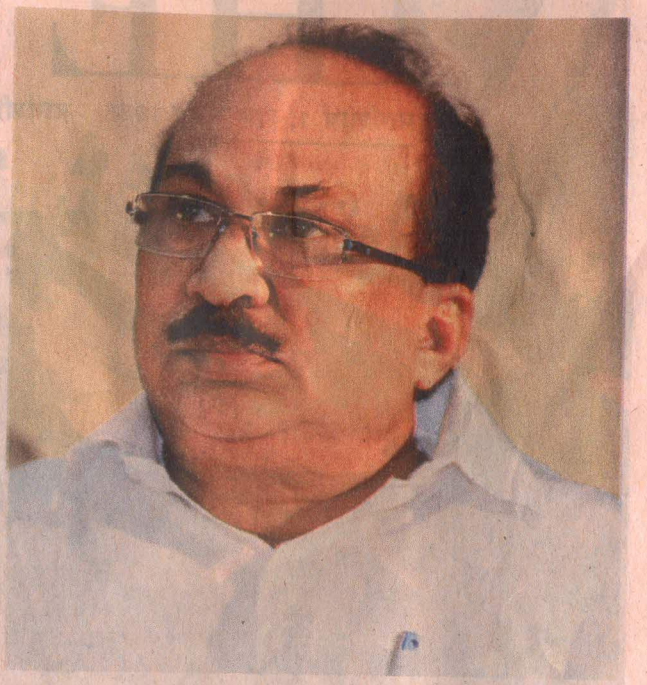

Economic Times
22/11/13